In those areas also, futures or hedge contracts are not being permitted at present, though there is no formal ban. There is no proposal to impose a ban formally."

मेरा प्रश्न यह है कि क्या पिछले हफ्ते में पश्चिमी बंगाल के जूट व्यापारियों ने फार्वर्ड मार्किट कमीशन के सामने ऐसा कोई सुझाव भेजा है कि उनको फ्यूचर्ज और हैज कांट्रेक्ट्स अमल में लाने की इजाजत दी जाए और अगर भेजा है तो सरकार ने उस पर या फार्वर्ड मार्किट कमीशन ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी यह नहीं देखा है। पिछले सप्ताह भेजा है तो शायद अभी यहां न पहुंचा हो। जब आएगा तब मैं उसको देखूंगा।

श्री अब्दुल गनी : जो वादा बाजारी करते हैं या जो सट्टा करते हैं क्या उनको लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि कितना सट्टा हुआ है ? क्या उनको सरकार को कोई इत्तिला देनी पड़ती है, अगर देनी पड़ती है तो क्या देनी पड़ती है ? अगर उनको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है तो क्या सरकार सोचेंगी कि उनको कोई न कोई लाइसेंस लेना पड़े सरकार से बाकायदा ताकि सरकार को पता चले कि इस वक्त रुई का या बाकी खाने पीने की चीजों का क्या हाल है ।

[جو وعدہ بازاری کرتے ھیں یا سٹہ کرتے ھیں کیا ان کو لائسنس لینا پڑتا ھے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کتنا سٹہ ھوا ھے - کیا ان کو سرکار کو کوئی اطلاع دینی پڑتی ھے - اگر دینی پڑتی ھے تو کیا دینی پڑتی ھے - اگر ان کو لائسنس نہیں لینا پڑتا ھے تو کیا سرکار سوچے گی کہ ان کو کوئی نہ کوئی لائسنس لینا پڑے سرکار سے باقاعدہ تاکہ سرکار کو پتہ چل سکے کہ اس وقت روئی کا یا باقی کھانے کی چیزوں کا کیا حال ھے -]

श्री दिनेश सिंह : कुछ चीजों में तो कमिशन ने निर्धारित कर रखा है कि कौन कौन सी एसोसिएशंज हैं जिन के जरिये फार्वर्ड मार्किटिंग हो सकता है। सब का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या नहीं, मैं एक दम नहीं कह सकता।

Shri Ranga: Contrary to what was suggested by one of our friends here one of the Members put a supplementary—is it not a fact that the forward prices of groundnut and groundnut and groundnut oil are lower than the ready market rates and they are not higher than the ceiling or the fair price fixed by the Government?

Shri Dinesh Singh: I could not say off-hand the prices that hon. Member may have in mind on a particular day but I will certainly find out.

Shri Ranga: Thank you.

Imported Raw Materials

+

*692. Shri B. S. Sharma:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Ram Singh Ayarwal:

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there are some industrial units which are totally dependent on the imported raw materials;

(b) if so, whether as a result of the restriction imposed by Government to import the required raw material, certain units had to close down;

(c) whether Government propose to take any steps to provide indigenous

raw material on priority basis so as to make these units run; and

(d) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Raghunath Reddi): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, except in the case of one cork products unit which closed down only recently.

(c) and (d). It is not possible to replace imported corkwood from within the country which is the raw material for cork products.

श्री भोलाशंकर शर्मा : क्या मंत्री महोदय ऐसी औद्योगिक इकाइयों के नाम बताने की कृपा करेंगे जो इस तरह के इम्पोर्टिड रा मैटीरियल पर निर्भर करती हैं और क्या वे ऐसी औद्योगिक इकाइयों के नाम बताने की भी कृपा करेंगे कि जो गत वर्ष इम्पोर्टिड रा मैटीरियल के न मिलने के कारण बन्द हो गई थीं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि जवाब में कहा गया है जहां तक हमारी इनफार्मेशन है सिर्फ एक इंडस्ट्री इम्पोर्टिड रा मैटीरियल के न मिलने की वजह से बन्द हुई है। लेकिन जो लिस्ट आप मांगते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इम्पोर्टिड रा मैटीरियल के ऊपर डिपेंड करती हैं, वह लिस्ट बहुत लम्बी है और अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं और चाहें तो मेज पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेज पर रख दें।

श्री भोलाशंकर शर्मा : जहां तक सेफ्टी रेजर ब्लेड्स को बनाने का सवाल है जो कम्पनियां इसको बनाती हैं वे इम्पोर्टिड रा मैटीरियल पर ही डिपेंड करती हैं। यह एक ऐसी चीज है जो रोजमर्रा के काम में आती है और इसके बिना हम सब सूखी और साबू बन जाएंगे। यह एक आवश्यक और जरूरी इकाई है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए देश में ही कच्चा माल बनाने का मंत्री महोदय ने क्या कोई प्रयत्न किया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि आनरेबल मैम्बर को मालूम होगा हमारी पालिसी इसकी बाबत बिल्कुल साफ है : जो प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो भी रा मैटीरियल की जरूरत है और कम्पोनेंट पार्ट्स की जरूरत हैं उसके लिए फारेन एक्सचेंज मिल सकता है। जितना फारेन एक्सचेंज अवेलेबल है उसका तीन चौथाई से ज्यादा रुपया इन इंडस्ट्रीज के लिए दिया जा रहा है और बाकी जो एक चौथाई है वह उन इंडस्ट्रीज के लिए दिया जात है जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती हैं लेकिन जो आवश्यक हैं। इन तमाम बातों पर डी० जी० टी० डी० गौर करता है और गौर करके फारेन एक्सचेंज देने की सिफारिश करता है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : ये जो फैक्ट्रीज बन्द हुई ये कितने दिनों तक बन्द रहीं और इसमें कितना नुक्सान हुआ होगा ? स्वदेशी माल देने की वजह से क्या इनके द्वारा जो चीजें उत्पादित होती हैं उनके भावों पर भी कोई असर पड़ेगा अगर पड़ेगा तो कितना ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा मैंने कहा है बन्द तो सिवाय एक के कोई नहीं रही लेकिन रा मैटीरियल न मिलने की वजह से प्रोडक्शन कई इंडस्ट्रीज में कम हुआ। इसकी लिस्ट भी मेरे पास है और वह भी मैं मेज पर रख दूंगा।

श्री ओंकार लाल बेरवा : स्वदेशी रा मैटीरियल जो आप दे रहे हैं इसकी वजह से क्या भावों पर भी कोई असर पड़ेगा, क्या भाव भी बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो कितने ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। जब प्रोडक्शन कम होता है, खर्चा अधिक होता है तो कीमतों पर जरूर असर पड़ता है।

लेकिन अगर आनरेबल मैम्बर के खयाल में कोई खास इंडस्ट्री है तो उसका नाम वह मुझे बतायें और मैं मालूम करके बता सकता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र कन्नाय : छोटे उद्योगों को तथा जो आवश्यक उद्योग हैं उनको हमने काफी सहायता दी है । क्या यह सही नहीं है कि इन में बहुत सी फर्जी फैक्ट्रीज भी हैं जिन को लोन तथा सहायता प्रदान कर दी गई है ? कागजों पर ही ये फैक्ट्रियां थीं लेकिन एक्चुअली नहीं थीं और इनको लोन व सहायता दी गई, क्या यह सच नहीं है ? क्या यह भी सच नहीं है कि इस तरह जो सरकारी पैसा था वह डूबा ? यदि हां तो इस तरह के कितने कारखाने हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब आप स्वदेशी कच्चा माल देंगे तो देश में तैयार माल के भाव में वृद्धि होगी, तो इस वृद्धि रोकने के लिए सरकार कौन से विशेष कदम उठाने जा रही है ताकि भावों में वृद्धि न हो ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जिन इंडस्ट्रीज को जितने रा मैटीरियल की जरूरत थी है उनको वह पूरा मिल चुकता और उनका प्रोडकशन भी पूरा होता तो भाव नहीं बढ़ सकते हैं । भाव उसी हालत में बढ़ा जबकि थोड़े दिन रा मटीरियल नहीं मिला था और उसकी वजह से वे इंडस्ट्रीज बन्द थीं । अभी जो हमारे पास फिगर्ज हैं उन से मालूम होता है कि जून 1966 से जो पालिसी हमने अख्तयार की उसके बाद से काफी इंडस्ट्रीज को रा मैटीरियल और कम्पोनेंट पार्टस मिल रहे हैं और उनकी जो आइडल कैपेसेटी थी, वह यूज हो रही है और भावों पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र कन्नाय : मैंने पूछा था कि ऐसी भी बहुत सी फर्जी फैक्ट्रीज थी जिन को लोन वगैरह दिये गये थे, ऐसी भी फैक्ट्रीज थीं जो कागजों पर थीं और जिन को लोन आदि मिले ? क्या इसके बारे में कोई शिकायतें सरकार को मिली थीं कि कारखाने कागजों में हैं, असल में ये कायम नहीं हुए हैं ? ऐसे कितने कारखाने हैं जो आपके ध्यान में आए हैं ? यह मैंने पूछा था ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सावल तो दूसरा है । इस का इस के कोई ताल्लुक नहीं है ।

Shrimati Lakshmikanthamma: May I know what progress has been made in raising the production of indigenous raw materials such as copper? May I know whether the Ministry does any co-ordination and, from time to time, evaluation of the progress made in the copper mines and other sources of scarce raw materials so that we are able to produce indigenous raw materials to a great extent ?

Shri F. A. Ahmed: Sufficient work is being done in order to bring about substitution of raw materials which we are now importing from outside, and for that purpose incentive has been provided to all those who are in a position to give us the know-how and to those who are in a position to produce those raw materials in our country. A Board has also been set up in order to determine those cases on merit so that those actually making effort in those directions are given the prizes for the effort that they are making in this direction. So far as copper is concerned, it is a raw material which we cannot easily get in our country. Therefore, we are depending in a big way on the import of this raw material from outside. If there is any possibility we shall certainly try to utilise that opportunity of increasing availability within the country of the raw materials of copper also.

Shri Hem Barua: May I know if Government have assessed the likely impact of the closure of Suez Canal on our imports, and since there is a

lot of idle capacity in our engineering industry today, whether in the public sector or private sector, and industries that have to depend mainly on imported raw material, may I know the extent to which this industry is going to suffer because of the closure of Suez Canal?

Shri F. A. Ahmed: So far as the present position is concerned, I think the hon. Member is aware that these licences are given in some cases on a six-monthly basis and in other cases on an yearly basis. And, so far as my present information goes no industry has been affected in respect of the arrival of the orders already placed for the raw materials and component parts. But, certainly, if the Suez Canal continues to remain closed it will have the effect of stopping inflow and when the industries will not get the raw material or component parts the production will undoubtedly suffer.

Shri Umanath: Sir, in today's papers, one Shri Wanchoo, I think a Commerce Ministry official, is reported to have stated that the industrialists are adopting a double-faced policy with regard to import substitution. On the one hand they welcome import substitution, and, on the other, in actual practice, they go and press the Government to give them import permits for machinery and raw materials which are available and which could be purchased internally. Textile machinery is produced here, but the Government is giving permits to import textile machinery from abroad. When the industrialists are adopting a double-faced policy, I would like to know why the Government is also adopting a double-faced policy in so far as they give permits to import raw materials or machinery which are available internally? Why should the Government adopt such a policy? Why should they give permits to import when the material is available here? I would like to know the reasons.

Shri F. A. Ahmed: This matter is receiving my closest attention. I can assure the hon. Member that all those components which are manufactured within our country and all the raw materials that are available within our country, will not be allowed to be imported.

Shri Umanath: Textile machinery is available here. Why should they give permits to import textile machinery?

Shri F. A. Ahmed: I have already said that I am examining this, and wherever I find that such machinery is indigenously manufactured in our country, it will not be allowed to be imported.

Shri Umanath: He has allowed the import of textile machinery which is produced here. *Why did he allow it?* Let him give the reason for allowing it.

Shri F. A. Ahmed: I did not allow any but as I have already said that some cases have been brought to my notice when this was permitted in the past and I am trying to see that in future this is not done.

श्री सरजू पाण्डेय : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कांसे और तांबे के बर्तन बनते हैं, लेकिन वह सारा उद्योग कांसा और तांबा न मिलने की वजह से बन्द है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है? यदि हां, तो क्या उस उद्योग को चलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष व्यवस्था हो रही है या नहीं।

श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैं ने पहले जवाब में कहा है, जहां तक काप्पर का ताल्लुक है, वह चीज़ काफी स्केयर्स है और जहां तक मुमकिन हो सकता है, हम उस को बाहर से लाने की कोशिश करते हैं। अगर काप्पर न मिलने की वजह से कोई इंडस्ट्री बन्द है, तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उस को किस तरह से यह रा मैटीरियल दिया जावे।

श्री राम चरण : मैं यह जानना चाहता हूं कि जितना रा मैटीरियल इम्पोर्ट किया जाता है और मनुफैक्चरर्ज को सप्लाई किया जाता है, वे लोग उस को एक्चुअली यूज करते हैं या उस को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, क्या सरकार की ओर से इस बात को चैक करने की कोई व्यवस्था है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि कोई माल ब्लैकमार्केट में बेचा जाता है। मैं आनरेबल मेम्बर की इत्तिला के लिए यह भी कह सकता हूं कि जहां तक छोटी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, पहले जब उन को रा मैटीरियल की जरूरत होती थी, तो वे इधर-उधर से ले लिया करते थे, लेकिन जब से हम ने अपनी पालिसी बदली है और हम स्माल स्केल-इंडस्ट्रीज को रा मैटीरियल और कम्पोनेंटस देने लगे हैं, जिस से उन की जरूरत पूरी हो जाती है, तब से ब्लैक मार्केटिंग का रास्ता भी बन्द हो गया है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि हमारे देश में राइस मिल मशीनरी आज से नहीं, बल्कि प्री-वार टाइम से तैयार हो रही है, परन्तु फिर भी राइस मिल मशीनरी जापान या अन्य देशों से लाई जाती है ; यदि हां, तो इस का क्या कारण है? ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं इस का कारण नहीं बता सकता हूं, लेकिन अगर राइस मिल की मशीनरी हमारे मुल्क में बन रही है....

श्री मधु लिमये : इस में अगर की क्या बात है? मंत्री महोदय तथ्य बतायें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है। वह अगर मगर कर रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वह नहीं बता सकते हैं। अगर वह नहीं बता सकते हैं, तो क्या बाहर से कोई आ कर बतायेगा? वह मिनिस्टर हैं, वह तन्ख्वाह ले रहे हैं। उन को पूरी जानकारी रखनी चाहिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : आनरेबल मेम्बरों ने जवाब पूरा होने से पहले ही टोक दिया है।

इस का इन्हसार सप्लाई और डिमांड पर है। जो चीज हम यहां पैदा कर सकते हैं, वह जरूर यहां से दी जायेगी। उस के अलावा जिस चीज की जरूरत है, अगर वह हमारे यहां मुहैया नहीं हो सकती है, तो हो सकता है कि उस को बाहर से मंगाया जाये।

Shri Virendrakumar Shah: Import licences are issued by the Commerce Ministry for the needs of the industries under the Industries Ministries here. Is the hon. Minister aware of the fact that under the AID and other licensing arrangements there are certain procedural formalities which require a long time, sometimes 8 to 10 months, before the import licence is granted to the applicant industry and even after that such conditions are put that the industries do not have sufficient imported raw materials for them to carry on? What does the Government propose to do to see that all these difficulties are obviated now?

Shri F. A. Ahmed: As I have already said, all these matters are gone into by the licensing committee. After the licensing committee has cleared the case as regards the actual requirements and whether they are indigenously available or not, then the case goes to the Commerce Ministry for allocation of funds for the purpose of import out of the foreign exchange available. For that purpose they have a list of 59 industries which have to be given first priority. There is also a list of non-priority industries.

Shri Virendrakumar Shah: Sir, he has answered it in the other direction. The question is that delays take place and because of that the companies come to almost closure. Has the Minister's attention been drawn to that and, if so, what is the Government planning to do to solve it? I did not ask about this rigmarole of going to this committee or that committee.

Shri F. A. Ahmed: Except in one case, no question of closure has been brought to my notice.

Shri Vasudevan Nair: Is the hon. Minister aware that last year large quantities of natural rubber were allowed to be accumulated in India and when there was an accumulated stock of indigenous rubber, import was allowed....

Mr. Speaker: We had a half-an-hour discussion on this question.

Shri Vasudevan Nair: Still, the issue remains unsolved and we will have to raise it again and again.

Was it a fact that large quantities of natural rubber were imported when there awas accumulated stock of rubber indigenously produced in the country; if so, what was the reason for the same?

Shri J. B. Kripalani: Somebody must have got commission.

Shri F. A. Ahmed: The hon. Member may give notice of a separate question and then I will be able to answer this.

Shri Vasudevan Nair: He is not aware of anything. Why should he answer questions like this? He should come prepared because we will ask many questions on import.

Shri F. A. Ahmed: How does rubber arise out of this question?

Mr. Speaker: Import. Shri Kothari.

Shri S. S. Kothari: What are the criteria on the basis of which you licence such industries which require entirely imported raw material?

Shri F. A. Ahmed: There are certain industries which are entirely dependent on imported raw materials and if they are of the category such as forged crank shaft, gear and radiator industries, power cables, enamelled copper winding wires and transformers, electric motors, switchgears, capacitors, rectifiers.....

Shri S. S. Kothari: I have asked for the principles not the list.

Shri F. A. Ahmed: I am just coming to that. Whatever foreign exchange is asked for the purpose of importing raw material and component parts for the requirements is given entirely for these things.

Shri Bedabrata Barua: While the private sector is allowed a lump sum of foreign exchange for importing their necessities the public sector enterprises are at a disadvantage as they have to make an indent of their requirements in advance and because they have to give all their requirements for the year in advance it leads to their inventories being overstocked which is considered to be the main cause for the losses of public enterprises.

Shri F. A. Ahmed: As I have said, it depends on the kind of industry. In some cases we are supplying foreign exchange for six months; in other cases for the whole year. The nature of the components and raw material required in public undertakings is such that unless and until we know the picture for the entire year it is not possible for us to determine what will be their requirements and that they will suffer in production if those things are not available to them. Therefore, on the basis of annual requirements, those component parts and raw materials are provided for the public undertakings. So far as private undertakings are concerned, it differs from industry to industry. In some cases on the basis of six months and in other cases on the basis of one year it is given.